

**न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)****पीठासीन अधिकारी - प्रभा गौतम (आर.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या 166/2022(नि.पं.) (GCMS 2022/166)	दायर दिनांक 07.07.2022	निर्णय दिनांक 19.12.2025
--	---------------------------	-----------------------------

**अनवान**

1. श्रीमती सुरजी पुत्री रामेश्वर उर्फ रमेश राव उम्र 26 वर्ष पेशा खेती निवासी नपावली तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्रीमती प्रेमबाई पत्नी रामेश्वर उर्फ रमेश राव उम्र 60 वर्ष पेशा खेती निवासी नपावली तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।
3. रामेश्वर उर्फ रमेश राव उम्र 70 वर्ष पेशा खेती निवासी नपावली तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।

**निगराकारान****बनाम**

1. ग्राम पंचायत नपावली, जरिये ग्राम विकास अधिकारी (सचिव) ग्राम पंचायत नपावली तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्रीमती मांगीदेवी पत्नी बंशीलाल राव, उम्र वयस्क निवासी नपावली तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।

**गैर-निगराकारान**

उपस्थिति :- दिनेश शर्मा  
एक तरफा  
अनुपस्थित

निगराकार  
गैर-निगराकार संख्या 1  
गैर-निगराकार संख्या 2

**निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम, 1994  
वास्ते निरस्त किये जाने पट्टा नंबर 11 दिनांक 16.04.12013  
ग्राम पंचायत नपावली**

**--:: निर्णय ::--**

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि निगराकार ने एक निगरानी प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरुद्ध गैर-निगराकारान के विरुद्ध अधीनस्थ ग्राम पंचायत नपावली पंचायत समिति भदेसर द्वारा जारी पट्टा जो कि गैर-निगराकार संख्या एवं निगराकार संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया है के संबंध में प्रस्तुत की गई है।

इस पर निगरानी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर-निगराकारान को जरिये नोटिस के तलब किया गया एवं अधीनस्थ ग्राम पंचायत नपावली से मूल अभिलेख तलब किया गया। दिनांक 09.05.2024 को गैर-निगराकार संख्या 01 के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से गैर-निगराकार संख्या 01 के विरुद्ध कार्यवाही



एक तरफा अमल में लाई गई। दिनांक 05.06.2024 को गैर-निगराकार संख्या 02 के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से गैर-निगराकार संख्या 02 की अनुपस्थिति रिकार्ड की गई। विकास अधिकारी भदेसर द्वारा पत्रांक/पसभ/संस्थापन/2023-24/204 दिनांक 19.05.2024 से अधीनस्थ ग्राम पंचायत नपावली को रिकार्ड प्रेषित किया जो कि पत्रावली के हम किता होकर रिकार्ड पर है। में रेकार्ड उपलब्ध नहीं है। उक्त पत्र शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। प्रकरण में बहस पत्रावली को सुना गया।

सर्वप्रथम विद्वान अधिवक्ता निगराकार ने अपनी बहस पत्रावली में निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि मौजा नपावली में प्रार्थीगण का पैतृक भूखण्ड स्थित है। भूखण्ड पर प्रार्थीगण का मकान बना होकर मकान के आगे खुली जगह पर लकडिया, खाद की रोडी व मवेशी बांधकर प्रार्थीगण करीब 50 वर्षों से अधिक समय से उपयोग-उपभोग करते चले आ रहे हैं। इसी भूखण्ड का ग्राम पंचायत ने विपक्षी संख्या 2 को अनियमित एवं अवैधानिक रूप से पट्टा जारी कर दिया जो निरस्त होने योग्य है। भूखण्ड का पट्टा प्राप्ति के लिये पंचायत अधिनियम अनुसार धारा 145 के अन्तर्गत आवेदन पंचायत द्वारा प्राप्त किया जाता है और धारा 146 के अनुसार लगातार स्थल निरीक्षण के लिये पंचायत द्वारा आवेदन को रजिस्टर में दर्ज कर फाईल खोली जाती है एवं तीन पंचों की सहमति बना कर स्थल निरीक्षण कर 15 दिवस में रिपोर्ट पंचायत की कौरम में पेश किया जाना आवश्यक होता है। इस निरीक्षण रिपोर्ट में इसी धारा की खण्ड (3) के अनुसार अपनी राय देना आवश्यक होता है लेकिन विवादित पट्टा नंबर 11 के लिये की गई कार्यवाही में इस धारा में वर्णित प्रावधानों की अनदेखी कर पट्टा जारी किया जो निरस्त होने योग्य है।

धारा 147 के अनुसार आपत्ति नोटिस प्रकाशित कराया जाना आवश्यक है और नोटिस की प्रति भूखण्ड पर लगाई जाना आवश्यक है लेकिन विवादित भूखण्ड के प्रकरण में पंचायत द्वारा पालना नहीं कर पट्टा जारी किया गया जो निरस्त होने योग्य है। विवादित पट्टे के लिये विपक्षी संख्या 2 द्वारा कोई आवेदन भूखण्ड का नाप तौल और कब्जा पुराना होने के संबंध में कोई तथ्य आवेदन में नहीं दिये तथा पंचायत ने भी स्थल निरीक्षण नहीं कराया केवल मात्र धारा 157(1) के प्रावधानों के तहत बिना किसी सबूत के प्रार्थीगण के स्वत्व एवं कब्जेशुदा भूखण्ड को विपक्षी संख्या 2 का मानकर केवल मात्र 200/- रुपये राशि में जमा कर पट्टा जारी कर दिया जो अवैधानिक होकर निरस्त होने योग्य है जबकि विवादित स्थल आम सड़क के पास होकर काफी बेश कीमती है लेकिन विपक्षी संख्या 2 ने सरपंच से दुर्भिसंधी कर यह पट्टा प्राप्त कर लिया जो निरस्त होने योग्य है।

पट्टा दिनांक 16.04.2013 को जारी होना बताया गया लेकिन इस बाबत की गई सारी प्रक्रिया को खुले रूप से नहीं अपना कर गोपनीय तरीके से वास्तविक तथ्यों को छुपा कर अवैधानिकता कर पट्टा जारी किया जो निरस्त किये जाने योग्य है। पंचायत नियमों एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार भूमिहीन परिवार तथा आवेदनकर्ता के पास पूर्व में मकान है या नहीं जिसकी जांच करने के बाद परिवार के एक सदस्य को ही पट्टा जारी किया जा सकता है लेकिन प्रस्तुत प्रकरण में विपक्षी संख्या 2 के परिवार



का बहुत बड़ा मकान गांव के मध्य में है। इस तथ्य की पंचायत ने कोई जांच नहीं कर प्राथीगण के कब्जेशुदा भूखण्ड व मकान को विपक्षी संख्या 2 का पुराना मकान मानकर विवादित पट्टा जारी कर दिया जबकि इस स्थल पर प्राथीगण का मकान बना हुआ होकर विपक्षी ने कनेक्शन प्रार्थी नंबर 3 के नाम से लिया हुआ है। पंचायत की समस्त कार्यवाही पंचायत नियमों के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत होने से पट्टा निरस्त होने योग्य है।

पट्टा दिनांक 16.04.2013 का जारी होना बताया गया है लेकिन प्राथीगण को इसकी किसी प्रकार से जानकारी नहीं थी। प्रथम बार दिनांक 25.08.2010 को विपक्षी नंबर 2 ने अपने नाम पंचायत का पट्टा होने का कहते हुए जबरन अतिक्रमण करने का असफल प्रयास किया। इस कथन के बाद प्राथीगण ने पंचायत में आवेदन किया लेकिन मात्र पट्टा नंबर 11 की ही प्रतिलिपी उपलब्ध कराई गई। इसके बाद प्रार्थी ने कानूनी सलाह प्राप्त कर आर्थिक व्यवस्था कर यह निगरानी पेश की है। ऐसे अवैधानिक कार्यवाही व पट्टों को निरस्त कराने के लिये कोई मियाद निश्चित नहीं की गई है और न्याय सिद्धान्तों के अनुसार भी अवैधानिक फर्जी व शून्य आदेशों व निर्णयों के लिये मियाद कानूनी से बाधित नहीं होता फिर भी जो देरी हुई है जानकारी के अभाव में एवं कोरोना काल आ जाने से हुई। इसलिये न्यायहित में देरी माफ करने हेतु अलग से दफा 5 कानून मियाद का प्रार्थना-पत्र व शपथ-पत्र अलग से पेश है। गैर-निगराकार को पट्टा जारी करने बाबत वैध प्रक्रिया की अनुपालना नहीं की गई है। आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं करते हुए विधि की अवज्ञा का नियम विरुद्ध पट्टा जारी किया गया है जो गलत होकर निरस्त किये जाने योग्य है अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर गैर-निगराकार को जारी पट्टा को निरस्त फरमाया जावे। इसी ईशतदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता निगराकार ने अपनी बहस समाप्त की। हमने पत्रावली का गहनतापूर्वक आद्यौपांत अवलोकन किया। तथ्यों का चिंतन-मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। प्रकरण में तथ्यों का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। हमने विधि का अवलोकन किया पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 97 का गहनता पूर्वक परिशीलन किया :-

**97. Power of revision and review by Government.-** (1) The State Government may, either of its own motion or on an application from any person interested, call for and examine the record of a Panchayati Raj Institution or of a Standing Committee or Sub-Committee thereof in respect of any proceedings to satisfy itself as to the correctness, legality or propriety of any decision or order passed therein or as to the regularity of such proceedings and, if in any case, it appears to the State Government that any such decision or order be modified, annulled, reversed or remitted for reconsideration, it may pass order accordingly:

Provided that the State Government shall not pass any order prejudicial to any party unless such party has a reasonable opportunity of being heard in the matter.

(2) The State Government may stay the execution of any such decision or order prejudicial to any party, pending the exercise of its powers under sub-section (1) in respect thereof.



(3) The State Government may, of its own motion or on an application received from any person interested, at any time within ninety days of the passing of an order under Subsec.

(1), review any such order if it was passed by it under any mistake, whether of fact or of law or in ignorance of any material fact. The provisions contained in the proviso to Sub-sec. (1) and in Sec. (2) shall apply to a proceeding under this sub-section.

राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अनुसार राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध व्यक्ति के आवेदन पर किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी समिति की किन्ही भी कार्यवाहियों के संबंध में निर्णय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता, औचित्य एवं नियमित होने की दृष्टि से अभिलेख मंगाने, परीक्षण करने एवं ऐसे आदेश/निर्णय/कार्यवाही प्रस्ताव को संशोधित करने, उलट दिये जाने, उपांतरित किये जाने या पुनः विचारार्थ प्रतिप्रेषित किये जाने की अधिकारिता रखती है। राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ4(10)परावि/विधि/संशोधन/2004/3690 दिनांक 13.12.2004 के अनुसार उक्त धारा 97 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रत्यायोजन जिला कलक्टर को पुनर्स्थापित कर दिया गया है। निगराकार द्वारा हस्तगत निगरानी में विवादित पट्टे के संबंध में उसकी विधिकता/औचित्य के संबंध में प्रश्न उठाया गया है, ऐसी स्थिति में हस्तगत निगरानी इस न्यायालय में पोषणीय पाया जाता है।

हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख की अवलोकन/परिशीलन किया। पंचायतीराज नियम 1996 के अध्याय 9 में आबादी भूमि के संबंध में प्रक्रियात्मक प्रावधान किये गये हैं। उक्त प्रावधानों के अनुसार नियम 157 के तहत पुराने गृहों का विनियमितीकरण किये जाने के प्रावधान प्रावधित किये गये हैं। पंचायतीराज नियम, 1966 के नियम 157 में निम्नानुसार प्रावधान प्रावधित किये गये हैं।

#### 157. Regularisation of old houses.-

[1][Where the persons are in possession of the old houses in Abadi land and desire to get a patta issued, patta may be issued by the Panchayat in Form XXIII-A after depositing the charges as under : -

- |   |           |
|---|-----------|
| (a) For old houses constructed more than fifty years before the date of commencement of these rules             | Rs. 100/- |
| (b) For old houses constructed [during the seventy years immediately preceding to date of 31st December, 2016]. | Rs. 200/- |

[2][Provided that no fees shall be charged under sub-clause (a) an only 10 percent fees shall be charged under sub-clause (b) of clause (i) above from the families included in the list of below poverty line.]

हमने अधीनस्थ ग्राम पंचायत बानसी से प्राप्त अभिलेख का गहनता से अध्ययन/परिशीलन किया। राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 में पुराने गृहों को विनियमितकरण के संबंध में प्रावधान प्रावधित किये गये हैं। प्रावधानुसार जहाँ व्यक्तियों के कब्जे से आबादी भूमि में पुराने गृहों हो और वे पंचायत से कोई पट्टा जारी करवाना चाहते हो तो वह नियमानुसार राशि कराये जाने के पश्चात् पंचायत द्वारा पट्टे जारी



किया जा सकेगा। यहाँ यह तथ्य महत्वपूर्ण के है कि ग्राम पंचायत को राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 में आबादी भूमि में स्थित पुराने गृहों विनियमितीकरण के संबंध में प्रावधान प्रावधित किये गये है। उक्त प्रावधानों के तहत ग्राम पंचायत को केवल मात्र आबादी भूमि स्थित गृहों के विनियमितीकरण किये जाने की ही क्षेत्राधिकारिता है गैर आबादी भूमि के संबंध में ग्राम पंचायत को किसी भी प्रकार के कोई अधिकार राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 द्वारा प्रदान नहीं किये गये है।

हमने अधीनस्थ ग्राम पंचायत नपावली द्वारा प्रस्तुत मूल अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत अभिलेख में भूखण्ड के संबंध में कोई पत्रालवी/मिसल तैयार नहीं की गई है। मिसल के अभाव में पट्टा जारी किये जाने के संबंध में प्रक्रियात्मक प्रावधानों का परीक्षण किया जाना संभव नहीं है। मिसल के अभाव में भूखण्ड के संबंध में पट्टवारी रिपोर्ट/किस्म भूमि प्रमाण-पत्र, ग्राम पंचायत नपावली द्वारा जारी सूचना पत्र बाबत् आबादी भूमि में स्थित पुराने गृह के विनियमितीकरण के संबंध में आरोप आमंत्रित करने का अनापत्ति पत्र किस दिनांक को जारी किये गये यह स्पष्ट नहीं हो पाया है, ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष यह तथ्य प्रकट होता है कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत नपावली द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 में पुराने गृहों को विनियमितीकरण के संबंध में प्रावधानों की पूर्ण रूप से अवहेलना किया जाना जाहिर होता है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर उक्त विवादित पट्टा जारी किया जाना जाहिर होता है, ऐसी स्थिति में जाहिर आता है कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत नपावली पंचायत समिति भदेसर द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 के तहत पुराने गृहों के विनियमितीकरण के प्रावधानों के तहत आवेदक को पट्टा जारी किये जाने में विधिक भूल की जाकर पट्टा जारी किये जाने में अधीनस्थ ग्राम पंचायत नपावली द्वारा त्रुटि कारित की गई है।

पत्रावली पर इस संबंध में किसी भी प्रकार से कोई युक्ति-युक्त कार्यवाही अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा की नहीं किया जाना प्रतिवेदित होता है। प्रकरण में आवेदकों के प्रार्थना-पत्र(आवेदन पत्र/मिसल) भी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। भूखण्ड के संबंध में पट्टवारी रिपोर्ट/किस्म भूमि प्रमाण-पत्र नहीं है। ग्राम पंचायत नपावली द्वारा जारी सूचना-पत्र बाबत् आबादी भूमि प्रस्तावित विक्रय संबंध में आक्षेप आमंत्रित किये जाने वाले प्रारूप को किस रीति से व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया है यह स्पष्ट नहीं होता है। प्रथम दृष्टवा ही यह मात्र खाना-पूर्ति प्रतीत होता है। इसके साथ ही गैर-निगराकारान द्वारा बावजूद किसी भी प्रकार से कोई खण्डन प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे है, ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष यह तथ्य प्रकट होता है कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत नपावली द्वारा हस्तगत विवादित पट्टा जारी किये जाने में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियमों एवं प्रावधानों की पूर्ण रूप से अवहेलना किया जाना जाहिर होता है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर उक्त विवादित पट्टा जारी किया जाना जाहिर होता है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत नपावली पंचायत समिति भदेसर द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों के तहत आवेदक को पट्टा जारी किये



जाने में विधिक भूल की जाकर पट्टा जारी किये जाने में अधीनस्थ ग्राम पंचायत नपावली द्वारा त्रुटि कारित की गई है। पंचायतीराज अधिनियम की धारा 97 के तहत पंचायतीराज संस्था या उसकी किसी समिति की किन्ही भी कार्यवाहियों के संबंध में निर्णय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता के परीक्षण का ही प्रावधान है, ऐसी स्थिति में विवादित पट्टे को खारीज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर निगराकार द्वारा उठाये गये ग्राम पंचायत नपावली पंचायत समिति भदेसर द्वारा विवादित पट्टा संख्या 11 नपावली द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों के तहत आवेदक को पट्टा जारी किये जाने में विधिक भूल की जाकर पट्टा जारी किये जाने में अधीनस्थ ग्राम पंचायत नपावली द्वारा त्रुटि कारित किया जाना प्रकट होता है, ऐसी स्थिति में निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार किया जाता है, एवं अधीनस्थ ग्राम पंचायत आव्या द्वारा जारी पट्टा संख्या 11 दिनांक 16.04.2013 जो कि गैर-निगराकार संख्या 02 श्रीमती मांगीदेवी पत्नी बंशीलाल राव, उम्र वयस्क निवासी नपावली तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) के पक्ष में जारी किया गया है को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति विकास अधिकारी भदेसर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **19.12.2025** को लिखाया जाकर सुनाया गया।



(प्रभा गौतम)  
अतिरिक्त कलक्टर,  
(प्रशासन) चित्तौड़गढ़